People Act, 1951, relating to registration of political parties, should not be deleted and there should be a specific provision to de-register a party if it violate the undertaking given under the section. The power to de-register should vest in the High Court.

18. The provisions of section 28 of the Representation of the People Act, 1950 and section 169 of the Representation of the People Act, 1951, are violative of and repugnant to the provisions of article 324 of the Constitution. The authority to make rules should therefore, be conferred totally on Election Commission. The Election Commission shall, however, consult the Central Government.

मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बायो-गैस संयंत्र

7062. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्थापित किये गये बायो-गैस संयंत्रों की जिलेवार संख्या और ब्यौरा क्या है ;

(ख) वर्ष 1994 के दौरान छत्तीस गढ़ क्षेत्र के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में बायो-गैस संयंत्र स्थापित करने के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ग) उक्त अवधि के दौरान स्थापित किये गये बायो-गैस संयंत्रों की कुल संख्या कितनी है ; और

(घ) सरकार द्वारा बायो-गैस स्थापित करने के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) वर्ष 1991-92 से 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में परिवार आकार के कुल 6,733 बायो-गैस संयंत्र स्थापित किये गये हैं। राष्ट्रीय बायो-गैस विकास परियोजना के तहत वर्ष 1991-92 से 1993-94 के दौरान जिला-वार और वर्ष-वार स्थापित संयंत्रों की संख्या विवरण में दी गई है। (**नीचे देखिये**)।

(ख) भारत सरकार ने 1994-95 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य के लिये अस्थायी तौर पर 15,000 परिवार आकार के बायो-गैस संयंत्रों का लक्ष्य निर्धारित किया है। राष्ट्रीय बायो-गैस संयंत्र परियोजना के तहत परिवार आकार के बायो-गैस सयंत्रों की स्थापना के लिये वास्तविक लक्ष्य का जिलावार आवंटन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(ग) वर्ष 1991-92 से 1993-94 की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश राज्य ने राष्ट्रीय बायो-गैस विकास परियोजना के तहत परिवार आकार के कुल 27,208 बायो-गैस संयंत्र स्थापित किये गये हैं।

(घ) वर्ष 1991-92 से 1993-94 के वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश राज्य को कुल 7.70 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई थी जो निम्न प्रकार से है:-

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये)
1991-92	1.53
1992-93	1.70
1993-94	4.47
जोड़ :	7.70

विवरण

वर्ष 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के तहत मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्थापित परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	स्थापित संयंत्रों की संख्या			
		1991–92	1992–93	1993–94	जोड़
1.	अम्बिकापुर	36	70	136	242
2	बिलासपुर	80	226	452	758
3.	बस्तर	7	150	756	913
4.	दुर्ग	45	61	148	254
5.	रायगढ़	120	285	700	1105
6.	रायपुर	869	901	1212	2982
7.	राज नन्दगांव	71	208	200	479
		1228	1901	3604	6 733

Projects undertaken for development of Non-conventional energy sources in Karnataka

7063. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what are the Projects undertaken for development of non-conventional energy sources in Karnataka;

(b) the Agencies and firms which have been licensed to manufacture solar energy equipments in Karnataka and subsidy given to these Agencies; and

(c) what are the facilities and subsidies available to those who want to establish industries to manufacture solar energy and other non conventional energy equipments.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI S. KRISHNA KUMAR): (a) In addition to the on-going extension programmes on Biogas, Improved Chulha and Solar Cookers, Installation of 468 biomass gasifier systems, 11 Community/Institutional/Night soil based Biogas plants, a 2 MW capacity demonstration wind farm project, 22 small hydro projects aggregating to about 24.15 MW, 287 solar photovoltaic systems, 2 solar photovoltaic pumps for irrigation, 22606 sq.m. of solar thermal collector area and 7 urjagram projects have been taken up in the State of Karnataka for utilisation of non-conventional energy sources.

(b) and (c) Agencies and firms are not required to seek any licence from the Ministry of Non-Conventional Energy Sources to set up a unit for producing solar energy equipment. Facilities available to industries for manufacture of non-conventional energy equipments include concessional custom duty on selected items of materials & equipment and soft loans through Indian Renewable Energy Development Agency Exemption from payment of sales tax & exise duty also forms part of these facilities. Under the photovoltaic pumping programme for irrigation, a subsidy at the rate of Rs. 170 per peak watt is available to manufacturers and market intermediaries for photovoltaic pumps supplied by them to users at subsidised costs.